राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

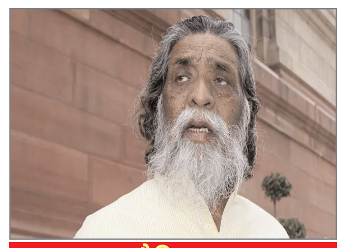

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 07 फरवरी 2026
वर्ष 14, अंक 288, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

नहर माइनर की पटरी कटी, पानी गांवों में घुसा, 50 बीघा फसल जलमग्न..03

पंचायत सचिव खोजवा ड्यूटी के दौरान शराब ठेके से एक पेटी शराब लेते हुए वीडियो वायरल..04

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे प्रशांत किशोर, CJI सूर्यकांत ने पटना लौटाया, बोले- लोगों ने रिजेक्ट किया तब याद आई?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रशांत किशोर की जनसुराज को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कथित फ्रीबीज को लेकर बिहार चुनावों को रद्द करने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को जन सूरज पार्टी की याचिका सुनवाई हुई. इस दौरन सीजेआई सूर्यकांत ने जनसुराज को फटकार लगाई और कहा कि हारी हुई पार्टी के कहने पर अदालतों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. आप वापस पटना हाईकोर्ट जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. प्रशांत किशोर की जनसुराज की दलीले सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा. सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं।

जनसुराज ने क्या-क्या कहा?

वहीं, याचिकाकर्ता ने दलील कि जब राज्य में आचार संहिता लागू था, उस दौरान महिलाओं को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किया गया. इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह महिलाओं की सहायता के लिए जारी राशि का हिस्सा था. सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ वकील चंद्र उदय सिंह ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि यह तय समय पर सोच समझकर किया गया और यह सभी महिलाओं के लिए हो गया जिनके पति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं हैं. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव याचिका में एक चुनाव को मुद्दा बनाया जाता है. आप तो एक ही याचिका में पूरा चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं. इसकी योग्यता नहीं है।

जनसुराज की क्या दलील?

प्रशांत किशोर की पार्टी के तरफ से पेश वकील ने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है. अदालत को इसमें हस्तक्षेप कर जवाब तलब करना चाहिए. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने साफ कर दिया कि हम नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. क्या थी याचिका में डिमांड? दरअसल, जनसुराज की ओर से दायर याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी. जनसुराज की याचिका में 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राज्य की एक कल्याणकारी योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने चुनाव हारने के बाद राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करने की कोशिश करने पर जनसुराज को फटकार लगाई. प्रशांत किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आपको कितने वोट मिले? जब लोग आपको नकार देते हैं, तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं! किसी को तो उस समय ही योजना को चुनौती देनी चाहिए थी. यह हमारे सामने प्रार्थना नहीं है. आप बस चुनाव को रद्द घोषित करवाना चाहते हैं.' खास बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला करने के लिए हाईकोर्ट सही मंच है. सीजेआई ने कहा, 'चूंकि यह सिर्फ एक राज्य से जुड़ा मामला है, इसलिए कृपया उस हाई कोर्ट में जाएं.कुछ मामलों में मुफ्त योजनाओं का गंभीर मुद्दा है जिसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे।'

जनसुराज की दलीलः जन सुराज पार्टी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कहा कि जिस योजना के तहत मतदाताओं को भुगतान किया गया था, उसे चुनावों से ठीक पहले घोषित किया गया था और भुगतान तब किया गया जब आचार संहिता लागू थी. सीयू सिंह ने तर्क दिया, 'लेकिन जब किसी राज्य में गंभीर वित्तीय घाटा हो और यह एक तरह की खैरात हो कि 10,000 रुपये तुरंत दिए जाएंगे और आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद 35 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना में नामांकित हो गए.' CJI ने जवाब दिया कि डायरेक्ट ट्रांसफर योजना अलग है. यह महिला स्वयं सहायता समूहों के बारे में है. कोर्ट ने कहा कि हालांकि वह मुफ्त योजनाओं के मुद्दे की जांच करेगा, लेकिन उसे याचिकाकर्ता की नेकनीयती भी देखनी होगी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हम मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर विचार करेंगे. लेकिन हमें नेकनीयती भी देखनी होगी... हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते जो अभी-अभी चुनाव हारी है. जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे.' इसके बाद जनसुराज ने याचिका वापस ले ली. याचिका के अनुसार, इस योजना के लिए पात्रता महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप के नेटवर्क, जीविका की सदस्यता से जुड़ी थी. राज्य सरकार ने घोषणा की कि जो महिलाएं पहले से जीविका का हिस्सा नहीं हैं, वे भी लाभ पाने के लिए एनरोल कर सकती हैं।

दिल्ली हिंसाः पुलिस को कोर्ट का नोटिस, आरोपी की जमानत याचिका पर मांगा जवाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के मामले में 2 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की कोर्ट ने आरोपी अतहर खान और सलीम मलिक की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए. दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 3 मार्च को करेगी.

सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप सह-आरोपी सलीम खान और शादाब अहमद जैसे ही हैं, जिन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. अथर खान के वकील ने भी कहा कि उनके मुवक्किल को सलीम खान के बराबर मानते हुए जमानत मिलनी चाहिए।

कोर्ट ने ट्रायल के लिए मांगा रिकॉर्ड

वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से वकील ध्रुव पांडे ने कहा कि यह कहना कि आरोपियों की स्थिति जमानत पाने वालों जैसी ही है, शायद सही नहीं है. मामले में नोटिस जारी करते हुए, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मांगा और साफ़ किया कि अगली तारीख पर मामलों में कोई रोक नहीं दी जाएगी. दरअसल, दंगा आरोपियों ने UAPAमामले में जमानत देने से इनकार करने के 29 जनवरी के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

2020 का है पूरा मामला

आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे. फरवरी 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे 'बड़ी साजिश' रचने के आरोप में गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप हैं. इस मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशारत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा (2021 में बेल मिली), शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर (इंसानियत के आधार पर बेल मिली क्योंकि गिरफ्तार होने के समय वह प्रेग्नेंट थीं), शरजील इमाम, फैजान खान, देवांगना कलिता (बेल मिली) और नताशा नरवाल (बेल मिली) आरोपी हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

वंदे भारत एक्सप्रेस में लगी आग, धुआं देखकर घबराए लोग; रेलवे की तकनीकी जांच पर उठे सवाल

चक्रधरपुर रेल मंडल में हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी सामने आने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। ट्रेन के पहियों में आग लगने की घटना के बाद रेलवे प्रशासन को आनन-फानन में ट्रेन रोकनी पड़ी और यात्रियों को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया।

यात्रियों में अफरा-तफरी

दरअसल, चक्रधरपुर रेल मंडल के टुनिया रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा-राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया, जब इंजन से तीसरे कोच के पहियों में हॉट एक्सल के कारण आग लग गई। घटना के बाद पहियों से धुआं उठने लगा, जिसे देखकर ट्रेन में सवार यात्रियों में घबराहट फैल गई। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और वंदे भारत एक्सप्रेस को टुनिया रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मौके पर पहुंची तकनीकी टीम ने आग पर काबू पाया और कोच की मरम्मत की। इस घटना से चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में भी हलचल मच गई। हैरानी की बात यह रही कि टाटानगर और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पहले ही जांच की जा चुकी थी, इसके बावजूद चक्रधरपुर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हो गई।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार सभी यात्रियों को ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा-पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस में शिफ्ट कर राउरकेला भेजा गया। बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस के खाली रैक को राउरकेला पहुंचाया गया। इधर, राउरकेला से हावड़ा जाने वाली ट्रेन संख्या 20872 वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने टाटानगर से एक अलग वंदे भारत रैक राउरकेला मंगाया। इसके बाद यह ट्रेन शाम करीब साढ़े चार बजे राउरकेला के प्लेटफॉर्म नंबर पांच से रवाना हुई। इस पूरी घटना के कारण यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। चक्रधरपुर रेल मंडल में पहले से ही ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान हैं। अब वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में तकनीकी खराबी की घटना से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है।

UP में SIR की मियाद फिर बढ़ी, अब 10 अप्रैल को जारी होगा फाइनल वोटर लिस्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के लिए जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई है. यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज शुक्रवार को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तारीख बढ़ाने का ऐलान करते हुए बताया कि इसे एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर कई दल तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे. अब 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज बताया कि उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर दावे और आपत्ति करने की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है. इसे एक और महीने के लिए बढ़ाया गया है. उन्होंने बताया कि 5 फरवरी तक 82,684 फॉर्म-7 तो 37,80,414 फॉर्म-6 को 6 जनवरी से 4 फरवरी तक जमा कराया गया है. इसी तरह से 1073 ओवरसीज से एप्लीकेशन आए हैं. उन्होंने बताया कि सबसे अधिक फॉर्म्स 5 फरवरी को जमा कराए गए, इस दिन 3 लाख से ज्यादा फॉर्म्स आए।

राजनीतिक दलों ने की थी तारीख बढ़ाने की मांग

एसआईआर की मियाद बढ़ाए जाने को लेकर नवदीप रिणवा ने बताया कि 27 जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में तारीख फिर से बढ़ाने की मांग आई थी और सभी इस पर सहमत थे कि समय बढ़ाया जाना चाहिए. इसीलिए इसमें एक महीने का समय बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों का समय एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. नोटिस का जवाब और सत्यापन के लिए एक महीना का वक्त बढ़ाया गया है. अब 6 मार्च तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 जमा करवा सकते हैं. नोटिस के सुनवाई की प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी. 27 मार्च तक मैपिंग करवाया जा सकेगा और नोटिस का जवाब दे सकेंगे. जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित होगी।

ड्रॉफ्ट लिस्ट में 12.55 करोड़ से अधिक वोटर्स

चुनाव आयोग की ओर जारी आंकड़ों में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत अब तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटर्स की संख्या 12,55,56,025 थी. इसमें Form 6 की संख्या 54,37,850 थी तो फॉर्म 7 की संख्या 1,33,650 रही. BLAs की ओर से जमा किए गए फॉर्म 6 की संख्या 37,789 रही तो ?आम नागरिकों की ओर से जमा किए गए फॉर्म 6 और 6 A की संख्या 37,81,487 थी. ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जमा कराए गए फॉर्म 6 की कुल संख्या 38,19,276 थी तो ड्राफ्ट जारी होने से पहले जमा कराए गए फॉर्म 6 की संख्या 16,18,574 थी. ?4 फरवरी तक कुल फॉर्म 6 की संख्या 54,37,850 थी।

IPS अधिकारी शंकर चौधरी पर विजिलेंस का शिकंजा, दर्ज की FIR, लगे गंभीर आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली विजिलेंस यूनिट ने IPS अधिकारी शंकर चौधरी (AGMUT: 2011 बैच) के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की है. यह मामला दिल्ली में बिना अनुमति छापेमारी, अवैध हिरासत और संपत्ति की कथित हेराफेरी से जुड़ा है. जांच के दौरान IPS अधिकारी को लेकर कई बातें सामने आई हैं. विजिलेंस पुलिस स्टेशन, बाराखंभा रोड में दर्ज FIR नंबर 02/2026 में IPS अधिकारी पर IPC की धारा 166, 341, 342 और 409 के तहत केस दर्ज किया गया है. यह FIR 21 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुई घटनाओं को लेकर दर्ज की गई है।

क्या हैं आरोप?

विजिलेंस जांच में सामने आया है कि IPS शंकर चौधरी ने दिल्ली में बिना किसी लिखित अनुमति या अधिकार क्षेत्र के छापेमारी करवाई की. चौधरी ने एक विदेशी नागरिक हैरिसन को चार दिन तक अवैध रूप से हिरासत में रखा. हैरिसन के घर से लॉकर और बैग जब्त किए, लेकिन न तो कोई सीजर मेमो बनाया न ही संपत्ति को मालखाने में जमा कराया. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और न ही कोई गिरफ्तारी रिकॉर्ड बनाया गया. यह हिरासत दिल्ली के मिज़ोरम हाउस, वसंत विहार में रखकर की गई, जो कानून के मुताबिक पूरी तरह अवैध मानी गई है।

CCTV और गवाहों से खुलासा

जांच में CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और 13 दिल्ली पुलिस कर्मियों के बयान दर्ज किए गए.फुटेज में साफ दिखता है कि 26 नवंबर 2023 की रात IPS अधिकारी हैरिसन के घर गए. करीब दो घंटे तक वो घर वो घर में रहे. हैरिसन को लॉकर और बैग उठाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया. इसके बाद हैरिसन को मिजोरम हाउस में रखा गया, जहां वह 26 से 29 नवंबर तक रहा।

35 लाख की वसूली का आरोप

29 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस के PCR पर एक महिला का फोन आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मिज़ोरम पुलिस ने उनके भाई को पकड़ लिया है और 35 लाख रुपये ले लिए हैं, वहीं अब 20 लाख रुपए और मांग रहे हैं. इस कॉल में IPS शंकर चौधरी का नाम सीधे तौर पर लिया गया. हालांकि कॉल करने वाली महिला का पूरा पता नहीं चल पाया, लेकिन कॉल की टाइमिंग और उसी रात हैरिसन की रिहाई ने मामले को और संदिग्ध बना दिया।

दिल्ली पुलिस कर्मियों की भूमिका

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने IPS अधिकारी की मदद की, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मंशा (mens rea) के ठोस सबूत नहीं मिले. इसलिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है, न कि आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।

विजिलेंस की सिफारिशें

ज्वाइंट CP (साउदर्न रेंज) एस. के. जैन, IPS ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि IPS शंकर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए. उनके खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई (Major Penalty Proceedings) शुरू की जाए. इसी सिफारिश के आधार पर 5 फरवरी 2026 को FIR दर्ज कर दी गई. इस मामले की आगे की जांच ACP विनय कुमार मलिक को सौंपी गई है. विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि यह केस पुलिस सिस्टम में अधिकारों के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है और इसकी जांच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी।

UP- 2 साल में एक लाख से ज्यादा लापता, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, सरकार को किया तलब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए खुद संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मुद्दे को जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज कर राज्य सरकार से विस्तृत आंकड़े और कार्ययोजना मांगी है. एक व्यक्तिगत मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में आया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक के लगभग दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में 1,08,300 से अधिक गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गई. इनमें से पुलिस ने मात्र 9,700 मामलों में ही कार्रवाई की और लोगों का पता लगाया. शेष अधिकांश मामलों में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. कोर्ट ने इन आंकड़ों को चौंकाने वाला और अत्यंत गंभीर बताते हुए पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई. बेंच ने कहा कि लापता व्यक्तियों की शिकायतें ऐसी हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्य में संस्थागत स्तर पर ही इसकी अनदेखी हो रही है।

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जानकारी

इस मामले को प्रदेश में गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में शीर्षक से जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर किया गया. राज्य सरकार के संबंधित विभागों से सभी आंकड़े, रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश. अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया।

रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई तय

कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिसमें जांच प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम शामिल होंगे. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने पारित किया. मूल मामले में एक पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी पर पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की थी, जहां FIR दर्ज होने में डेढ़ साल से अधिक समय लग गया था।

23 मार्च को होगी अगली सुनवाई

इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र के लिए बड़ी चुनौती है. यह फैसला उत्तर प्रदेश में लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाता है और उम्मीद है कि इससे जांच और ट्रैकिंग सिस्टम में सुधार होगा।

मेघालयः अवैध कोयला खदान में धमाके से 18 मज़दूरों की मौत, कइयों के फंसे होने की आशंका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में एक 'अवैध' कोयला खदान में गुरुवार (5 फरवरी) को हुए विस्फोट में कम से कम 18 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका है. उन्हें बचाने के लिए अभियान जारी है. इस बीच, मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने शुक्रवार (6 फरवरी) को कहा कि उनकी सरकार कोयला खदान में विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. संगमा ने कहा कि पुलिस को इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और चेतावनी दी है कि अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 3 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आई. नोंग्रांग ने गुरुवार को कहा, 'अब तक हमने 16 शव बरामद कर लिए हैं. विस्फोट के समय खदान के अंदर कितने मजदूर मौजूद थे, इसका अभी पता लगाया जा रहा है. और लोगों के फंसे होने की आशंका है.' खबरों के अनुसार, बाद में दो और मौतों की पुष्टि हुई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। अधिकारी ने बताया कि बचाव दल तलाश अभियान में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह घटना सुबह थांगस्कू इलाके में उस समय हुई, जब वहां कोयला खनन का काम चल रहा था, जिसे अवैध माना जा रहा है. पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार ने बताया कि विस्फोट में घायल हुए एक व्यक्ति को पहले सुतंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे शिलांग के एक अस्पताल में रेफर किया गया. जब उनसे पूछा गया कि क्या खदान अवैध रूप से चल रही थी, तो कुमार ने कहा, 'हां, ऐसा ही लगता है.' उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जाएगी. इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों से घटनास्थल का दौरा करने, अधिकारियों से मिलने और बचाव, राहत और कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया है।

दो खदान मालिक गिरफ्तार; बचाव अभियान जारी

अवैध रूप से संचालित कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद फंसे हुए माने जा रहे मजदूरों को निकालने के लिए जारी बचाव अभियान के बीच शुक्रवार (6 फरवरी 2026) को दो खदान मालिकों को गिरफ्तार किया गया. मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि सरकार अवैध रैट-होल खदानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा, 'अब तक 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है.' ज्ञात हो कि रैट-होल खनन - खदान में संकरी सुरंगों के जरिये कोयला निकालने की एक विधि है. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 2014 के आदेश के अनुसार यह भारत में प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें शामिल जोखिमों के कारण खनिकों की मौत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने विस्फोट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए दो कैबिनेट मंत्रियों को भी मौके पर भेजा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों से कहा गया है कि वे घटनास्थल का दौरा करें, अधिकारियों से मुलाकात करें और बचाव, राहत तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करें. बता दें कि पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध खनन के दौरान हादसे की ये पहली घटना नहीं है. जनवरी 2021 में जिले में एक कोयला खदान के अंदर काम करने के दौरान छह लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले दिसंबर 2018 में राज्य के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के कसन क्षेत्र में इसी तरह की एक खनन दुर्घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी. तब खदान में पास की नदी का पानी भर गया था, जिसकी वजह से खदान में काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस गए थे. करीब सात महीने के बचाव अभियान के बाद केवल तीन शव बरामद किए गए थे. इस दुर्घटना से पता चला था कि मेघालय में एनजीटी द्वारा साल 2014 में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी रैट होल खदानों में खनन जारी है. रैट होल खदान चूहों के बिल जैसी होती है, जिसमें संकरी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसके भीतर मजदूर जाते हैं और कोयला निकालकर लाते हैं. मेघालय हाईकोर्ट द्वारा गठित एक सदस्यीय समिति ने फरवरी 2025 में कहा था कि राज्य के छह कोयला समृद्ध जिलों में ऐसी गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं. मेघालय हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य में अवैध कोयला खनन बेरोकटोक जारी है, जिसमें 1.69 लाख मीट्रिक टन (एमटी) अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का पता चला है. समिति ने कहा था कि राज्य सरकार ने सितंबर 2022 के अदालती आदेश का अनुपालन करते हुए बताया कि मई और अगस्त 2022 के बीच पूर्वी जयंतिया हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स और पश्चिम खासी हिल्स जिलों में 92,268.43 मीट्रिक टन (एमटी) कोयला जब्त किया गया. राज्य सरकार द्वारा नियोजित निजी फर्म ने इन जिलों में अतिरिक्त 41,477.54 मीट्रिक टन कोयला दर्ज किया।

मलेशिया दौरा 2026: क्या बदलेगा एशिया का शक्ति-संतुलन?

क्या मलेशिया दौरा बदलेगा भारत की पूर्वी दिशा?
एक यात्रा, कई संभावनाएँ: मलेशिया की ओर भारत

जब एशिया की जियोपॉलिटिक्स अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा की तेज लहरों से घिरी हुई है, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7-8 फरवरी 2026 का मलेशिया दौरा एक साहसी, निर्णायक और दूरदर्शी कदम के रूप में उभरता है। यह यात्रा मात्र औपचारिक कूटनीति नहीं, बल्कि भविष्य की वैश्विक रणनीति को दिशा देने वाला ऐतिहासिक प्रयास है। अगस्त 2024 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने के बाद यह पहला बड़ा अवसर है, जब दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में हैं। अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर हुआ यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई ऊर्जा देगा और चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच संतुलन का स्पष्ट, सशक्त और आत्मविश्वासी संदेश भी प्रस्तुत करेगा। भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंध अब औपचारिकताओं की सीमाओं से निकलकर आपसी विश्वास, सहयोग और साझेदारी की गहराई तक पहुंच चुके हैं। लगभग 2.9 मिलियन भारतीय मूल के नागरिक मलेशिया में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। यही सशक्त डायस्पोरा भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर मजबूती प्रदान करता है। मोदी और अनवर की मुलाकात में व्यापार, निवेश, डिफेंस, सुरक्षा, डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे अहम विषयों पर ठोस और दूरगामी निर्णय होने की पूरी संभावना है। दसवां इंडिया-मलेशिया सीईओ फोरम इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण होगा, जहां भविष्य की आर्थिक साझेदारियों की मजबूत नींव रखी जाएगी। व्यापार के क्षेत्र में यह यात्रा एक निर्णायक और परिवर्तनकारी मोड़ साबित हो सकती है। मलेशिया का पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तेल-गैस संसाधन भारत की बढ़ती आवश्यकताओं को मजबूती देंगे, जबकि भारतीय आईटी, फार्मा और स्टार्टअप सेक्टर मलेशियाई बाजार में नए अवसरों की खोज करेंगे। दोनों देश व्यापारिक बाधाओं को कम करने, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था सुधारने और सप्लाई चेन को सशक्त बनाने पर ठोस सहमति बना सकते हैं। इंडो-पैसिफिक व्यापार गलियारों को गति देकर चीन पर निर्भरता घटाने का प्रयास भी इस एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मोदी का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है–व्यापार को केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति के रूप में विकसित करना। ऊर्जा क्षेत्र में यह दौरा भविष्य की हरित क्रांति की मजबूत आधारशिला रखने की पूरी क्षमता रखता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा संक्रमण पर सहयोग के नए द्वार खुलने की प्रबल संभावना है। मलेशिया के तेल और गैस संसाधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएंगे, जबकि भारत की उन्नत सोलर और विंड तकनीक मलेशिया को नेट-जीरो लक्ष्य के और अधिक निकट पहुंचाएगी। ऊर्जा संक्रमण से जुड़े संभावित समझौते दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक साझा और प्रभावी मोर्चे पर खड़ा करेंगे। यह साझेदारी आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का प्रेरणादायक उदाहरण बनेगी। मैरिटाइम सिक्योरिटी इस यात्रा का सबसे संवेदनशील, रणनीतिक और महत्वपूर्ण पक्ष है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के बीच भारत और मलेशिया का नौसैनिक सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य बन चुका है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना प्रमुख प्राथमिकता होगी। मलक्का जलडमरूमध्य की सुरक्षा वैश्विक व्यापार की जीवनरेखा है, जिसकी स्थिरता दोनों देशों के साझा हितों से जुड़ी है। यह सहयोग समुद्री सुरक्षा को नई दिशा देगा, जहां साझेदारी टकराव पर भारी पड़ेगी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नेतृत्व भूमिका इस दौरे के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावशाली होगी। एक्ट ईस्ट नीति और मलेशिया की लुक ईस्ट रणनीति का संगम एक मजबूत और संतुलित क्षेत्रीय ढांचा तैयार करेगा। इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर होने वाली चर्चा सुरक्षित, पारदर्शी और स्थिर व्यापार मार्गों के विकास में सहायक होगी। क्वाड, आसियान और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ समन्वय बढ़ने से क्षेत्र में संतुलित शक्ति व्यवस्था स्थापित होगी। मोदी का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है–इंडो-पैसिफिक को एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और सहयोगी क्षेत्र में परिवर्तित करना, जहां विकास और सुरक्षा साथ-साथ आगे बढ़ें। निवेश के क्षेत्र में यह यात्रा अवसरों के नए द्वार खोलने वाली सिद्ध होगी। मलेशियाई कंपनियां मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बन सकती हैं। सीईओ फोरम में होने वाले समझौते रोजगार सृजन, नवाचार और तकनीकी हस्तांतरण को नई गति प्रदान करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय निवेशकों और सरकारों के बीच एक मजबूत सेतु की भूमिका निभाएगा। मोदी की उद्योगपतियों से मुलाकात एफडीआई को विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करेगी। यह निवेश साझेदारी आपसी विश्वास, स्थायित्व और दीर्घकालिक सहयोग का मजबूत आधार बनेगी।सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में भी यह दौरा गहरा और दूरगामी प्रभाव डालेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और हेल्थ टेक में बढ़ता सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को मानवीय और संवेदनशील आधार प्रदान करेगा। महामारी के बाद हेल्थ टेक और वैक्सीन सहयोग की बढ़ती अहमियत इस साझेदारी को और सुदृढ़ बनाएगी। छात्र विनिमय कार्यक्रम और शोध साझेदारियां ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन-संपर्क से दोनों समाजों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। यह यात्रा प्रमाणित करेगी कि कूटनीति केवल समझौतों तक सीमित नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली निरंतर प्रक्रिया भी है। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा एक ऐतिहासिक, निर्णायक और दूरदर्शी क्षण के रूप में दर्ज होगी। यह दौरा व्यापार, ऊर्जा, डिफेंस, सुरक्षा और निवेश के नए युग की मजबूत नींव रखेगा। मोदी और अनवर के बीच की सकारात्मक केमिस्ट्री इन समझौतों को व्यवहारिक और प्रभावी रूप देगी। यह केवल दो देशों की औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य की दिशा तय करने वाला रणनीतिक प्रयास है। भारत-मलेशिया साझेदारी वैश्विक चुनौतियों के सामने एक सशक्त और अटूट दीवार बनकर उभरेगी। यह यात्रा उम्मीद, आत्मविश्वास और रणनीतिक दूरदृष्टि की प्रतीक बनकर इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी।

प्रो. आरके जैन

संपादकीय

कांग्रेस की वैचारिक उलझन और राष्ट्र के प्रति दायित्व संसद के शोर में दबता आत्ममंथन और इतिहास की सबसे बड़ी चूक

लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं होती, वह देश की सामूहिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का आईना भी होती है। हालिया बजट सत्र में लोकसभा के भीतर जो कुछ देखने को मिला, उसने इस आईने को धुंधला कर दिया। बार-बार का स्थगन, नारेबाजी, वेल में उतरना और संवाद के बजाय अवरोध की राजनीति यह सब किसी एक घटना या मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। यह एक गहरी वैचारिक बेचैनी का संकेत है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक धारा होने का दावा करती है।

कांग्रेस की विचारधारा ऐतिहासिक रूप से समावेशन, संस्थागत लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में यही पार्टी विभिन्न विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक मंच पर लाने में सफल हुई। लेकिन समय के साथ इस विचारधारा में स्पष्टता के बजाय विरोधाभास बढ़ते चले गए। आज संसद के भीतर कांग्रेस का आचरण यह सवाल खड़ा करता है कि क्या पार्टी अब भी उसी राष्ट्रीय दायित्वबोध के साथ राजनीति कर रही है, या वह केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए संस्थाओं को दबाव में लेने की रणनीति अपना चुकी है।

हालिया सत्र में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख की कथित किताब को लेकर कांग्रेस का रुख इसी उलझन को उजागर करता है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। लेकिन सवाल यह है कि सवाल किस मंच पर, किस भाषा में और किस उद्देश्य से उठाए जा रहे हैं। जब सदन में चर्चा की बजाय हंगामा प्राथमिक हथियार बन जाए, तो संदेश सरकार तक कम और जनता तक ज्यादा जाता है। यह संदेश यह होता है कि विपक्ष के पास तर्कों से अधिक शोर है।

कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यहीं से शुरू होती है। उसने धीरे-धीरे वैचारिक संघर्ष को व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक टकराव में बदल दिया। मुद्दों की गंभीरता को नारेबाजी की तीव्रता से मापा जाने लगा। चीन सीमा विवाद जैसा संवेदनशील विषय हो या अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता, इन पर राष्ट्रीय हित के व्यापक फ्रेम में बात करने के बजाय कांग्रेस अक्सर सरकार को कठघरे में खड़ा करने तक सीमित रह जाती है। इससे यह धारणा बनती है कि पार्टी का फोकस देश की रणनीतिक स्थिति पर कम और घरेलू राजनीतिक स्कोरिंग पर अधिक है।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने कई मौकों पर राष्ट्रीय हित के नाम पर बड़े फैसले लिए, लेकिन उतने ही मौकों पर उसने गंभीर भूलें भी कीं। सबसे बड़ी भूल सत्ता और संगठन के बीच संतुलन खो देना रही। एक समय जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र का उदाहरण मानी जाती थी, वही पार्टी धीरे-धीरे परिवार-केंद्रित राजनीति की प्रतीक बन गई। नेतृत्व का केंद्रीकरण इतना बढ़ा कि विचारधारा व्यक्तियों की छाया में सिमटती चली गई। इसका असर यह हुआ कि जमीनी स्तर पर बहस, असहमति और वैचारिक विकास ठहर सा गया।

संसद में बार-बार अवरोध पैदा करना इसी ठहराव का परिणाम है। जब पार्टी के पास दीर्घकालिक वैचारिक रोडमैप नहीं होता, तो वह तात्कालिक उत्तेजना के सहारे राजनीति करती है। कांग्रेस का यह रवैया कि 'बोलने नहीं दिया तो बोलने नहीं देंगे' सुनने में भले ही आक्रामक लगे, लेकिन यह लोकतांत्रिक आत्मविश्वास नहीं, बल्कि असुरक्षा का संकेत देता है। मजबूत विचारधारा वाली पार्टियां संवाद से भागती नहीं हैं, वे उसे दिशा देती हैं।

देश के प्रति निष्ठा केवल सरकार के समर्थन या विरोध से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि कठिन मुद्दों पर देश को कितना भरोसा दिया जा रहा है। जब संसद में सेना, कूटनीति या अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे विषयों पर चर्चा होती है, तो विपक्ष से यह अपेक्षा होती है कि वह सवाल पूछे, विकल्प रखे और सरकार को जवाबदेह बनाए। लेकिन जब वही विपक्ष इन मुद्दों को सदन ठप करने का माध्यम बना ले, तो राष्ट्रीय विमर्श कमजोर पड़ता है।

कांग्रेस की एक और बड़ी भूल यह रही है कि उसने समय के साथ बदलते भारत को समझने में देर की। आज का मतदाता केवल सरकार विरोधी नारे से संतुष्ट नहीं होता, वह समाधान और दृष्टि चाहता है। आर्थिक नीतियों, वैश्विक संबंधों और सुरक्षा चुनौतियों पर स्पष्ट स्टैंड चाहता है। कांग्रेस अक्सर इन विषयों पर प्रतिक्रिया देती दिखती है, पहल करते हुए कम। यही कारण है कि संसद के भीतर उसका विरोध कई बार नकारात्मक प्रतीत होता है, रचनात्मक नहीं।

यह भी सच है कि सरकार की जिम्मेदारी सदन को सुचारू रूप से चलाने की होती है और सत्ता पक्ष को भी संवाद के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। लेकिन विपक्ष का कर्तव्य इससे कम नहीं है। कांग्रेस यदि वास्तव में खुद को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहती है, तो उसे संसद को संघर्ष का अखाड़ा नहीं, विचारों का मंच बनाना होगा। उसे यह दिखाना होगा कि उसका विरोध केवल सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के पक्ष में है।

कांग्रेस की वैचारिक पुनर्रचना की जरूरत अब टलने वाली नहीं है। परिवार और प्रतीकों से आगे बढ़कर उसे नीतियों, संस्थाओं और भविष्य की दृष्टि पर लौटना होगा। संसद में शोर से ज्यादा असरदार होता है तर्क, और अवरोध से ज्यादा मजबूत होता है विकल्प। जब तक कांग्रेस यह नहीं समझेगी, तब तक उसके हर हंगामे के साथ यह सवाल और गहराता जाएगा कि क्या वह सचमुच देश के प्रति उसी निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ी है, जिसका दावा उसका इतिहास करता है।

आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें विपक्ष की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार को आईना दिखाने के साथ-साथ देश को भरोसा देना भी उतना ही जरूरी है। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का क्षण है। अगर वह अपनी बड़ी भूलों से सीख लेकर वैचारिक स्पष्टता और राष्ट्रीय दृष्टि के साथ आगे बढ़ती है, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा संसद का शोर इतिहास में केवल एक और चूके हुए अवसर के रूप में दर्ज हो जाएगा।

कांतिलाल मांडोत

एक मां, बीस जिंदगियां और अमर बलिदान

खुद बुझकर बीस दीप जलाने वाली मां
बीस मासूम सांसों की खातिर जली जीवन-ज्योति

रानापुर गांव की साधारण-सी मिट्टी पर उस दिन असाधारण इतिहास अंकित हुआ, जब एक सामान्य महिला ने अद्वितीय साहस दिखाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की कंचनबाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के उग्र झुंड के सामने अडिग दीवार बनकर बीस मासूम बच्चों की रक्षा की। वह न कोई सैनिक थीं, न अधिकारी, न योद्धा–फिर भी उस क्षण वे साहस, ममता और त्याग की जीवंत प्रतिमा बन गईं। हजारों डंक सहते हुए भी उन्होंने बच्चों को अपनी बाहों में समेटा, सुरक्षित कमरों तक पहुंचाया और स्वयं पीड़ा के अथाह सागर में डूबती चली गईं। उनका यह बलिदान केवल एक घटना नहीं, बल्कि नारी शक्ति की अमर गाथा है, जो सदियों तक समाज को दिशा और प्रेरणा देती रहेगी। कंचनबाई का जीवन संघर्षों की कठोर कसौटी पर गढ़ा गया था। पति गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी तरह उनके कंधों पर थीं। एक बेटा और दो बेटियों का भविष्य संवारना उनका प्रतिदिन का संकल्प था। आर्थिक तंगी, सामाजिक चुनौतियां और पारिवारिक दायित्व–सब कुछ उन्होंने मुस्कान के साथ निभाया। आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन बनाना उनके लिए केवल नौकरी नहीं, बल्कि बच्चों के प्रति स्नेह और सेवा का माध्यम था। वे हर बच्चे को अपने ही परिवार का हिस्सा मानती थीं। उनकी दिनचर्या में थकान थी, पर शिकायत नहीं; पीड़ा थी, पर निराशा नहीं। यही गुण एक साधारण स्त्री को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है।

जब मधुमक्खियों का झुंड बच्चों पर टूट पड़ा, तब कंचनबाई पास ही कपड़े धो रही थीं। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, न अपनी जान की परवाह की, न परिणामों का अनुमान लगाया। बिना किसी शोर, बिना किसी सहायता की प्रतीक्षा किए, वे दौड़ पड़ीं। बच्चों को दरी और तिरपाल में लपेटा, उन्हें ढाल बनाकर भीतर पहुंचाया और स्वयं खतरे के बीच अडिग खड़ी रहीं। यह क्षण महिलाओं की निर्णय क्षमता और मानसिक दृढ़ता का प्रतीक बन गया। संकट की घड़ी में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नारी कभी कमजोर नहीं होती, वह परिस्थिति आने पर सबसे मजबूत और विश्वसनीय कड़ी बन जाती है। मातृत्व की भावना कंचनबाई के व्यक्तित्व की आत्मा थी। वे केवल अपने बच्चों की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों की सजीव मां थीं। आंगनवाड़ी के वे मासूम चेहरे उनके लिए अपने ही परिवार का विस्तार थे। जब खतरा आया, तो उनका हृदय किसी अडिग कवच की तरह बच्चों के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने जीवन को तुच्छ समझकर बच्चों के भविष्य को सर्वोपरि रखा। यही मातृत्व का वास्तविक स्वरूप है–जहां स्त्री स्वयं को विस्मृत कर दूसरों का जीवन संवारती है। कंचनबाई ने मातृत्व को केवल जन्म तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे करुणा और संरक्षण का व्यापक, दिव्य रूप दिया। समर्पण कंचनबाई के जीवन का मूल मंत्र था। स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष के रूप में वे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में निरंतर लगी रहती थीं। वे दूसरों के दुख को अपना दुख समझती थीं और सहायता को अपना पवित्र कर्तव्य। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए भोजन बनाना उनके लिए सेवा और समर्पण का माध्यम था। उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को सामने नहीं रखा, बल्कि हर परिस्थिति में दूसरों को प्राथमिकता दी। मधुमक्खियों के हमले के समय भी उनका समर्पण चरम पर था–अपने जीवन की आहुति देकर उन्होंने समाज को बचाया। यही त्याग नारी को सभ्यता की सशक्त रीढ़ बनाता है।

करुणा और संवेदनशीलता कंचनबाई की आत्मा में गहराई से रची-बसी थी। वे हर पीड़ा को महसूस करती थीं, हर आंसू का मौन अर्थ समझती थीं। बच्चों की चीखें उनके हृदय को चीर गईं और उन्होंने बिना विलंब अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हजारों डंक उनके शरीर को घायल करते रहे, लेकिन उनकी चेतना बच्चों की सुरक्षा में अडिग लगी रही। यह करुणा महिलाओं का वह अमूल्य गुण है जो संसार को मानवीय बनाता है। जब समाज कठोर होता है, तब नारी की संवेदना उसे संतुलन और संवेदना प्रदान करती है। कंचनबाई ने यह सिद्ध किया कि करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है।

सहनशीलता कंचनबाई की पहचान थी। जीवन की कठिनाइयों–आर्थिक संकट, पति की बीमारी, पारिवारिक जिम्मेदारियां–को उन्होंने मौन साहस के साथ सहा। कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटीं। मधुमक्खियों के डंक उनकी त्वचा को जलाते रहे, लेकिन उनका संकल्प अडिग और अचल रहा। यह सहनशीलता महिलाओं को टूटने नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। वे दर्द को हृदय में समेटकर भी दूसरों को मुस्कान देती हैं। कंचनबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सहनशीलता से ही सच्चा साहस और आत्मबल जन्म लेता है।

कंचनबाई की वीरता आज पूरे क्षेत्र के लिए जीवंत प्रेरणा बन चुकी है। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व केवल पद से नहीं, बल्कि निःस्वार्थ कर्म से पैदा होता है। स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष के रूप में वे पहले ही नेतृत्व कर रही थीं, लेकिन उस दिन उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर सच्चा नेतृत्व दिखाया। गांव के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं और एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। उनकी शहादत ने समाज को गहराई से सोचने पर मजबूर किया है कि वास्तविक नायक वास्तव में कौन होते हैं।

आज आवश्यकता है कि समाज और सरकार कंचनबाई जैसे बलिदानों को केवल भावनात्मक श्रद्धांजलि तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सम्मान और स्थायी सुरक्षा में बदलें। उनके परिवार को आर्थिक सहायता, पेंशन, बच्चों की शिक्षा और रोजगार की ठोस व्यवस्था मिलनी चाहिए। यह सहायता दया नहीं, बल्कि एक वीरांगना को दिया गया सच्चा सम्मान होगी। जब हम ऐसी महिलाओं को उचित मान्यता देंगे, तभी समाज में साहस और सेवा की भावना सशक्त होगी। कंचनबाई की शहादत हमें यह सिखाती है कि नारी के गुण–साहस, करुणा, समर्पण, मातृत्व और सहनशीलता–ही सभ्यता की वास्तविक पूंजी हैं। उनकी स्मृति में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी बेटियों, माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे और उनके त्याग को कभी विस्मृत नहीं होने देंगे।

कृति आरके जैन

जाने चले जाते हैं कहाँ? लापता होने की अनसुलझी मिस्ट्री

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2026 की शुरुआत बेहद चिंताजनक रही है. दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक़ 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं. यानी लगभग हर रोज़ 54 लोग बिना किसी सूचना के गायब हो रहे हैं. इन लापता लोगों में सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां गायब हुई हैं. कुल मामलों में से लगभग 63% इसी श्रेणी के लोग हैं, बाकी पुरुष और लड़के हैं. यह आंकड़ा दिखाता है कि राजधानी में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है.

साल 2026 के सिर्फ शुरुआती पंद्रह दिनों के भीतर राजधानी दिल्ली से 800 से ज़्यादा लोगों का लापता हो जाना केवल एक चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता भी पैदा करता है.

खुद दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली से कुल 807 लोग लापता हुए. इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 54 लोग और लगभग हर घंटे में दो लोग राजधानी से गायब हो रहे हैं.807 लापता लोगों में 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं. यानी कुल मामलों में लगभग दो-तिहाई हिस्सा महिलाओं और किशोरियों का है. यह स्थिति उस शहर के लिए बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां पहले से ही कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं. दिल्ली पुलिस के अनुसार, अब तक केवल 235 लोगों का ही पता लगाया जा सका है, जबकि 3 फरवरी तक 572 लोग ऐसे थे, जिनके बारे में पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं थी.

दिल्ली पुलिस में दर्ज रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि नाबालिगों में किशोरियों (12-18 वर्ष) का अनुपात बहुत अधिक होता जा रहा है, जिससे यह समस्या और गंभीर हो गई है कि ये केवल रोजमर्रा के खो जाने के मामले ही नहीं हैं. कुछ मामलों में अपहरण या अन्य अपराधी गतिविधियों का भी खतरा हो सकता है. देश की राजधानी में रोज़ाना 50 से ऊपर लोग लापता होना सिर्फ आकड़ों का खेल नहीं है बल्कि यह हमारी सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर बड़े सवाल खड़े करता है. यह आंकडे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा की चुनौतियां गम्भीर रूप ले चुकी हैं. दिल्ली पुलिस आंकड़ों के अनुसार कुल 2026 के शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता दर्ज किए गए, वयस्कों के मामलों में 616 लोग लापता हुए, जिनमें 181 का पता चला (90 पुरुष और 91 महिलाएं), जबकि 435 वयस्क अभी भी लापता हैं. वहीं नाबालिगों के 191 मामले सामने आए, जिनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया (29 लड़कियाँ और 19 लड़के), जबकि 143 नाबालिग अब तक नहीं मिले हैं।

गायब होने वालों में महिलाओं और बच्चों की बढ़ती संख्या ने मानव तस्करी, अपहरण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संकटों की आशंका को गहरा कर दिया है. ये आंकड़े केवल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के असहनीय दर्द और समाज में बढ़ती असुरक्षा की परतों को भी उजागर करते हैं.

दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 807 लापता लोगों में 191 नाबालिग हैं. इनमें 146 लड़कियां और 45 लड़के हैं. पुलिस के अनुसार इन मामलों में से लगभग 71 प्रतिशत का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. आठ से बारह वर्ष की उम्र के 13 बच्चे और आठ वर्ष से कम उम्र के 9 बच्चे भी 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच लापता हुए हैं, जो हालात की गंभीरता को उजागर करता है. दरअसल, दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लापता लोगों से जुड़ी जानकारी सालाना आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट से मिलती रही है. अब तकनीक और केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणालियों के चलते ये आंकड़े तेज़ी से उपलब्ध हो रहे हैं. दिल्ली में लापता लोगों की समस्या कई वर्षों से चिंता का विषय बनी हुई है. बीते साल यानी 2025 में दिल्ली से कुल 24,508 लोग लापता हुए थे. इनमें 14,870 यानी 60 फीसदी से अधिक महिलाएं थीं. बीते दस वर्षों में दिल्ली से लगभग 2.51 लाख लोग गायब हुए हैं और इनमें से करीब 52,000 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है.

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में पूरे भारत में लगभग 8.68 लाख लोग लापता हुए थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरी केंद्रों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है. वर्ष 2024 में दिल्ली में लापता नाबालिगों की संख्या 5,846 थी, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 6,284 रहा था. पुलिस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पर इसके पीछे कई कारण सामने आते हैं. इनके अनुसार मौसमी पलायन, आर्थिक दबाव, बेरोज़गारी, पारिवारिक विवाद, घरेलू शोषण, मानव तस्करी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं गुमशुदगी के मामलों को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि , ''कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमने देखा है कि परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है. कई लोगों की नौकरियां छूटती हैं. फिर कर्ज और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं. महिलाओं और लड़कियों के मामले में घरेलू हिंसा, प्रेम प्रसंग में भागना और ट्रैफिकिंग बड़ा कारण है.'' एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लापता महिलाओं में से लगभग 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं मानव तस्करी का शिकार होती हैं. दिल्ली में प्रवासी आबादी बड़ी संख्या में रहती है और इन्हीं समुदायों से गुमशुदगी के मामले अधिक दर्ज होते हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क दिल्ली को अपना हब बनाते हैं, जिससे हालात और जटिल हो जाते हैं.

इतनी स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद पुलिस इन मामलों को प्रभावी ढंग से रोक क्यों नहीं पा रही? इस पर पुलिस अधिकारी का कहना है, ''आबादी के हिसाब से प्रभावी पुलिसिंग के लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं. इसके बावजूद पुलिस इस दिशा में अच्छा काम कर रही है. साल के शुरुआती 15 दिनों में लोगों के गायब होने के जिन आंकड़ों का हवाला आप दे रहे हैं, उनमें से तकरीबन 30 प्रतिशत का पता दिल्ली पुलिस ने लगा लिया. हमने ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विकसित किया है. इससे इन मामलों की ट्रैकिंग आसान हुई है. स्पेशल सेल और एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट इन मामलों पर तुरंत ही सक्रिय होती हैं. कई लापता लोग दूसरे राज्यों में मिलते हैं. इसलिए अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन और बेहतर बनाना जरूरी है.''

वैसे, दिल्ली सरकार के स्तर पर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी सक्रिय हैं. 2025 में आयोग ने लापता महिलाओं के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की थी. राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआरबी का लापता लोगों का डाटा है.

इन सबके बावजूद आंकड़े यही संकेत देते हैं कि मौजूदा प्रयास राजधानी में बढ़ती गुमशुदगी की समस्या को रोकने के लिए फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं. दिल्ली में लापता होते लोग केवल एक प्रशासनिक चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह संकट शहरी असमानताओं, सामाजिक असुरक्षा, अपर्याप्त संसाधनों, कमजोर कानून व्यवस्था और अदालत की अप्रभावी सहायता को भी उजागर कर रहा है .खासकर नाबालिग बालिकाओं की बड़ी तादाद में गायब होना उनके पीछे लवजेहाद अवैध ट्रैफिकिंग और तस्करी का अंदेशा प्रबल करती है। इस ओर गंभीर ध्यान देना होगा वरना असामाजिक तत्वों का सुनियोजित जाल नाबालिग बालक बालिकाओं के जीवन को अंधेरी सुरंग में धकेलता रहेगा।

मनोज कुमार अग्रवाल

दिल्ली में लापता होने की बढ़ती घटनाएँ

दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे सपनों की राजधानी कहा जाता है। देश के कोने.कोने से लोग यहाँ रोज़गारए शिक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं। ऊँची इमारतोंए चौड़ी सड़कों और तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी के बीच यह शहर लगातार फैल रहा है। लेकिन इसी चमक.दमक के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी हैए जो धीरे धीरे दिल्ली की पहचान पर सवाल खड़े कर रही है। यह सच्चाई है लोगों का गायब हो जाना। हर दिन दर्जनों लोग इस महानगर में लापता हो जाते हैं और उनमें सबसे अधिक संख्या किशोरियों और युवतियों की होती है। यह केवल अपराध का आंकड़ा नहींए बल्कि समाज के भीतर पनप रहे भयए असुरक्षा और टूटते विश्वास की कहानी है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में लापता होने के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन औसतन पचास से अधिक लोग गायब हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश पंद्रह से पच्चीस वर्ष की आयु के हैं। यह उम्र सपने देखने और भविष्य गढ़ने की होती हैए लेकिन यही उम्र सबसे अधिक खतरे में दिखाई देती है। खासकर लड़कियाँए जिनकी संख्या लड़कों की तुलना में कहीं अधिक है। कई मामलों में वे घर से पढ़ाईए काम या किसी जान.पहचान के व्यक्ति से मिलने के लिए निकलती हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटतीं। कुछ तो शुरुआती घंटों या दिनों में मिल जाती हैंए लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो महीनों और वर्षों तक नहीं मिलता। दिल्ली के कुछ इलाके इस संकट से विशेष रूप से जूझ रहे हैं। घनी आबादीए झुग्गी बस्तियाँए प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या और सामाजिक अस्थिरता इन क्षेत्रों को अधिक संवेदनशील बनाती है। यहाँ रहने वाले परिवार अक्सर गरीबीए बेरोज़गारी और घरेलू तनाव से घिरे रहते हैं। ऐसे माहौल में बच्चे और किशोर छोटी.छोटी बातों पर घर छोड़ देते हैं। लड़कियों के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। पारिवारिक दबावए पढ़ाई या विवाह को लेकर तनावए या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दिखाए गए झूठे सपने उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तकनीक के विस्तार ने जहाँ दुनिया को करीब लाया हैए वहीं उसने नए खतरे भी पैदा किए हैं। मोबाइल और सामाजिक मंचों के ज़रिये संपर्क बढ़ा हैए लेकिन इसी रास्ते से धोखा भी आसानी से दिया जा रहा है। नौकरीए मॉडलिंगए विवाह या प्रेम के नाम पर लड़कियों को फँसाया जाता है। कई बार उन्हें दूसरे शहरों या राज्यों में ले जाया जाता हैए जहाँ वे मानव तस्करीए जबरन श्रम या शोषण का शिकार हो जाती हैं। यह एक संगठित अपराध का रूप ले चुका हैए जिसमें सीमाओं की कोई परवाह नहीं की जाती। इस समस्या का एक बड़ा कारण पारिवारिक टूटन भी है। माता.पिता के बीच कलहए सौतेले रिश्तेए घरेलू हिंसा और भावनात्मक उपेक्षा बच्चों को असुरक्षित महसूस कराती है। जब घर सुरक्षित नहीं लगताए तो बाहर की दुनिया आकर्षक लगने लगती है। लड़कियों के लिए यह जोखिम और बढ़ जाता हैए क्योंकि समाज अब भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण नहीं दे पाया है। महामारी के बाद मानसिक तनाव और अवसाद की समस्याएँ भी बढ़ी हैं। युवा मन आसानी से बहक जाता है और गलत फैसले ले बैठता है। लापता होने का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। पूरा परिवार एक अनिश्चित पीड़ा में जीने लगता है। माँ.बाप हर अजनबी चेहरे में अपने बच्चे को ढूँढते हैं। आर्थिक बोझ बढ़ता हैए क्योंकि खोज.बीन में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। समाज में तरह.तरह की बातें बनने लगती हैंए जिससे परिवार और अधिक टूट जाता है। लड़कियों के मामलों में डर और भी गहरा होता हैए क्योंकि उनके साथ हिंसाए शोषण या मृत्यु की आशंका हर पल बनी रहती है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैंए जहाँ लापता होने के बाद हत्या या गंभीर अपराध का पता चला। सरकार और पुलिस ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर में निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैंए आपातकालीन नंबरों को मजबूत किया गया है और लापता व्यक्तियों की जानकारी साझा करने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता केंद्र बनाए गए हैंए जहाँ कानूनी और मानसिक सहयोग दिया जाता है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद समस्या की जड़ पर चोट नहीं हो पा रही। पुलिस बल की कमीए मामलों की संख्या का दबाव और राज्यों के बीच समन्वय की कमजोरी बड़ी बाधाएँ हैं। कई बार शुरुआती घंटों में कार्रवाई में देरी हो जाती हैए जो किसी भी लापता मामले में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह भी सच है कि योजनाओं और बजट की घोषणाएँ अक्सर कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं। ज़मीनी स्तर पर जागरूकता की कमी साफदिखाई देती है। बहुत से अभिभावक अब भी बच्चों के साथ खुलकर बात नहीं कर पाते। वे खतरे को समझते तो हैंए लेकिन उसे गंभीरता से लेने में चूक जाते हैं। लड़कियों को आत्मरक्षाए सुरक्षित व्यवहार और अपने अधिकारों की जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं दी जाती। समाज में यह सोच अब भी मौजूद है कि खतरा केवल बाहर हैए जबकि कई बार खतरा परिचित चेहरे के पीछे छिपा होता है।

इस समस्या का समाधान केवल पुलिस या सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह एक सामाजिक चुनौती हैए जिसका सामना सामूहिक प्रयास से ही किया जा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान सिखानी होगी। अभिभावकों को बच्चों के मित्र बनने की कोशिश करनी होगीए ताकि वे बिना डर अपनी बात साझा कर सकें। मोहल्ला स्तर पर निगरानी और सहयोग की भावना विकसित करनी होगी। अगर कोई बच्चा या किशोरी लंबे समय तक दिखाई न देए तो उसे सामान्य बात मानकर अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कानूनी स्तर पर भी सख्ती ज़रूरी है। लापता होने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई होए यह सुनिश्चित करना होगा। मानव तस्करी और शोषण से जुड़े अपराधों पर कठोर दंड और तेज़ सुनवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्यों के बीच बेहतर तालमेल से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति सीमा पार कर अपराधियों के हाथों में न जाए। साथ हीए लड़कियों को शिक्षा और रोज़गार के अवसर देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी उतना ही आवश्यक हैए क्योंकि आत्मनिर्भरता उन्हें निर्णय लेने की शक्ति देती है। दिल्ली को सच में सुरक्षित राजधानी बनाना हैए तो सोच बदलनी होगी। सुरक्षा केवल कैमरों और कानून से नहीं आतीए बल्कि भरोसेए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से आती है। हर नागरिक को यह समझना होगा कि किसी एक का गायब होना पूरे समाज की विफलता है। जब तक हम इस दर्द को अपना दर्द नहीं मानेंगेए तब तक आंकड़े बढ़ते रहेंगे और सपनों की यह राजधानी कई परिवारों के लिए डर का पर्याय बनी रहेगी। सतर्कताए संवाद और सामूहिक प्रयास ही इस साये को दूर कर सकते हैं। दिल्ली तभी आगे बढ़ेगीए जब उसकी बेटियाँ और बेटे बिना भय के घर से बाहर निकल सकें और सुरक्षित लौट सकें। यही सच्चा विकास हैए यही असली प्रगति।

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर त्रिवेदी की माता को दी गई श्रद्धांजलि

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के सातनपुर गांव में बुधवार को वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर त्रिवेदी की माता स्वर्गीय गोमती त्रिवेदी की तेरहवीं संस्कार संपन्न हुआ। शांति भोज में पत्रकार, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय गोमती त्रिवेदी का निधन 87 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके निधन की सूचना पर पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया। स्वर्गीय गोमती त्रिवेदी धर्मपरायण और सुसंस्कृत महिला थीं। उनका जीवन त्याग, संयम और नैतिक मूल्यों का उदाहरण रहा। वे पारिवारिक एकता और सामाजिक सौहार्द की समर्थक थीं। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अवनींद्र पांडेय, पवन द्विवेदी,शीतला प्रसाद गुप्ता, शनद द्विवेदी, सोनू मिश्रा, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ त्रिवेदी, संदीप कुमार फिजा, संतोष कुमार, टीके शुक्ला, शीतला गुप्ता, सुरेश श्रीवास्तव, रामबाबू गुप्ता, उमेश श्रीवास्तव, पूती मिश्रा, विमल तिवारी, जितेन्द्र सविता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

एक करोड़ 20 लाख से सरयू नदी पर तैयार होगा पीपा पुल, विभाग और एजेंसी के बीच हुआ एग्रीमेंट

अयोध्या। सरयू नदी में गुप्तार घाट के पास माझा जमथरा में पंचवटी द्वीप पर जाने के लिए पीपे का पुल निर्मित होने जा रहा है। निर्माण के लिए पुल का पीपा गिरने लगा है। निर्माण में लगभग एक माह लगेगा। इस पर एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत आएगी। वैसे वर्तमान में सरयू नदी लगभग सूख गई है। पंचवटी द्वीप वाले रास्ते पर सिर्फ सरयू की सोती का पानी बचा है। उसी को क्रास कर जाने के लिए दो सौ मीटर पीपे का पुल का निर्माण लोक निर्माण का प्रांतीय खंड कराएगा।

एजेंसी के बीच हुआ अनुबंध

प्रांतीय खंड के अनुसार टेंडर के बाद निर्माण के लिए विभाग और निर्माण एजेंसी के बीच अनुबंध हो गया है। पीपा गिरना शुरू है। यह पंचवटी द्वीप बीते दो वर्ष से निर्माणाधीन है। बताया गया कि पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए इसे निजी कंपनी तैयार कर रही है। यह कंपनी लखनऊ की बताई गई है, जिसे लीज पर भूमि दी गई है। श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए अत्यधिक वातानुकूलित वाले काटेज के अलावा बच्चों के लिए किड जोन, मेडिटेशन, रामायणकालीन पात्रों के अलावा पर्यटकों की मांग के अनुसार विभिन्न प्रांतों के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

UP में अब सात गुना कम खर्च पर मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, UPPCL ने की खास पहल

शुजागंज (अयोध्या)। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में सात गुना कम खर्च करना होगा। बिजली निगम ने फिक्स चार्ज की नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब तक उपभोक्ता के घर से बिजली पोल की दूरी 60 मीटर से अधिक होने पर नए पोल का एस्टीमेट बनता था, जिसमें 20 से 25 हजार रुपये का खर्च उपभोक्ता को उठाना पड़ता था, लेकिन नए प्रविधान के तहत बिजली निगम ने पोल दूरी की सीमा को 60 मीटर से बढ़ाकर 300 मीटर कर दिया है। इस दायरे में अब उपभोक्ताओं को केवल फिक्स चार्ज के आधार पर ही कनेक्शन मिलेगा। अधिशासी अभियंता रुदौली रोहित जैन ने बताया कि नई कास्ट बुक जारी कर दी गई है और सभी कर्मचारियों को इसके अनुरूप नए कनेक्शन देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ भी कम होगा। एक किलोवाट कनेक्शन पर 100 मीटर से अधिक दूरी होने पर 3500 रुपये फिक्स चार्ज जमा करने होंगे। विद्युत लाइन व पोल लगाने में जो खर्च आएगा, वह विभाग उठाएगा। अवर अभियंता रितेश वर्मा ने बताया कि नए प्रविधानों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलेगी। अब महंगे एस्टीमेट के कारण बिजली कनेक्शन से वंचित रहना नहीं पड़ेगा। नई व्यवस्था लागू होने से जहां एक ओर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली कनेक्शन मिलेगा, वहीं निगम की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा।

सोनभद्र रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों पर जिलाधिकारी सख्त, निष्क्रिय कार्यों को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र- कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला स्तरीय समिति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही मानवीय गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा की और व्यवस्थाओं में सुधार हेतु कड़े निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट किया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग पूरी तरह से पारदर्शी और जनहित में होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ कार्य लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं या कार्य बेकार पड़े हैं, उन्हें तत्काल नियमित और प्रभावी बनाया जाए। सोसाइटी के संसाधनों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाए। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु समाज के सबसे वंचित वर्गों की सहायता रहा। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा रेड क्रॉस सोसाइटी का मूल मंत्र मानव सेवा है। गरीब, असहाय और विशेषकर कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा, दवाइयां, वस्त्र और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहने दी जाए। बैठक में सोसाइटी की वित्तीय स्थिति, उपलब्ध बजट, वर्तमान आय-व्यय और भविष्य की जनहितकारी योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और जनहित के कार्यों में शून्य लापरवाही की नीति अपनाने की हिदायत दी। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से डॉ. पंकज कुमार राय मुख्य चिकित्साधिकारी, इन्द्रभान सिंह वरिष्ठ कोषाधिकारी, सुधांशु शेखर शर्मा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जय राम सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक, मुकुल आनन्द पाण्डेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी के अन्य सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

गिरिया गाँव में विराट रूद्र महायज्ञ का शंखनाद 51 फीट ऊंचे धर्मध्वज की हुई स्थापना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

चतरा, सोनभद्र। जनपद के चतरा ब्लॉक अंतर्गत गिरिया गाँव में आगामी विराट रूद्र महायज्ञ की तैयारियां अब परवान चढ़ने लगी हैं। गुरुवार को भक्तिमय वातावरण और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ स्थल पर 51 फीट ऊंचा धर्मध्वज स्थापित किया गया। इस ध्वज स्थापना के साथ ही पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्सव का माहौल बन गया है। यह विशाल यज्ञ भिक्षुक भिखारी, जंगली दास और रमाशंकर गिरी जी महाराज की पावन देखरेख में संपन्न होने जा रहा है। ध्वज पूजन के दौरान आचार्य देवी प्रसाद पांडेय, सतीश पांडेय, दीपक पांडेय एवं योगेश तिवारी ने शास्त्रोक्त विधि से पूजन संपन्न कराया। केसरिया ध्वज के आकाश चूमते ही भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण गुंजायमान कर दिया। जंगली बाबा ने यज्ञ की समय सारणी की जानकारी देते हुए बताया कि अनुष्ठान के मुख्य पड़ाव इस प्रकार होंगे। 06 मार्च भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके पश्चात कलश स्थापना के साथ यज्ञ का शुभारंभ होगा। 09 मार्च भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का विशेष आयोजन होगा। 14 मार्च यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में प्रवीण मिश्रा, सरिता मिश्रा, कृष्ण कुमार पुजारी और प्रभावती देवी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ध्वज स्थापना के इस पुनीत अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिनमें पूर्व प्रमुख रमाकांत पांडेय, आलोक मिश्रा, सुजीत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु शामिल थे।

बीजपुर थाने को मिला नया प्रहरी, नवागत थाना प्रभारी राजेश सिंह ने संभाली कमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सोनभद्र - जनपद के बीजपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा किए गए फेरबदल के बाद, गुरुवार की सायं नवागत थाना प्रभारी राजेश सिंह ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। उनके पदभार ग्रहण करने से पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है, वहीं स्थानीय जनता में सुरक्षा को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। थाने की कमान संभालते ही प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले थाने के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं मातहत कर्मचारियों के साथ परिचय बैठक की। इसके पश्चात उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों और बंदी गृह का बारीकी से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को टीम भावना के साथ पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए थाना प्रभारी राजेश सिंह ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि क्षेत्र में अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। शांति एवं आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम किया जाएगा ताकि आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। गरीब, असहाय और पीड़ित नागरिकों को समयबद्ध व निष्पक्ष न्याय दिलाना मेरा संकल्प है। न्याय के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजेश सिंह, थाना प्रभारी, बीजपुर एक औद्योगिक और संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ पुलिस की मुस्तैदी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजेश सिंह के रूप में एक अनुभवी नेतृत्व मिलने से उम्मीद जताई जा रही है कि क्षेत्र में जमीनी स्तर पर अपराधों में कमी आएगी और कानून का इकबाल बुलंद होगा।

हरदोई में सड़क हादसों में छात्रा समेत तीन लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हरदोई। तेज रफ्तार से वाहन चलाकर लोग खुद के साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार छात्रा की मौत हो गई। इसी तरह बिलग्राम और सांडी में बुधवार रात हुए हादसों में दो व्यक्तियों की जान चली गई। हादसों के बाद तीनों घटनाओं में चालक वाहन लेकर फरार हो गए। देहात कोतवाली के ग्राम खेतारी की पायल नौवीं की छात्रा थी। वह शहर स्थित राजकीय इंटर कालेज में पढ़ती थी। गुरुवार की सुबह साइकिल से विद्यालय आ रही थी। रास्ते में हरदोई-सीतापुर मार्ग पर मुरलीपुरवा के पास पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पायल गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक कार लेकर भाग गया। राहगीरों ने पायल को उपचार के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पायल दो भाइयों के बीच अकेली थी। दूसरी घटना में बिलग्राम के ग्राम झालापुरवा के रजनीकांत खेती करते थे। बुधवार को किसी काम से ग्राम बसहर गए थे। देर शाम बाइक से घर जा रहे थे। बसहर गांव के सामने अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हेलमेट लगाए थे,लेकिन हेलमेट सिर से निकलकर दूर जा गिरा,सिर में चोट आने से रजनीकांत की मौत हो गई। रजनीकांत के परिवार में पत्नी मीरा के अलावा एक बेटा अभिषेक है। वहीं सांडी के ग्राम बखरिया के वेदराम बुधवार की शाम मजदूरी कर साइकिल से घर जा रहे थे। कटरा-बिल्हौर हाईवे पर आटो ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। यहां वेदराम ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वेदराम के परिवार में पत्नी के अलावा पांच बच्चे हैं। थाना प्रभारी बसंतराम ने बताया कि तहरीर मिलने पर एफआइआर दर्ज की जाएगी।

कब्जेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप में तीन PCS अधिकारी सस्पेंड, वाराणसी के मंडलायुक्त बनाए गए जांच अधिकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। चंदौली जिले में सरकारी और गांवसभा की जमीन से जुड़े मामलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पता चला है कि कुछ अफसरों ने अवैध कब्जा हटाने के बजाय कब्जेदारों को फायदा पहुंचाया। इसी वजह से सरकार ने तीन पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तीनों ही अधिकारी पहले यहां तहसीलदार के रूप में तैनात थे। इन अधिकारियों पर सार्वजनिक, आरक्षित व ग्रामसभा भूमि को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। इनमें तत्कालीन तहसीलदार सतीश कुमार (वर्तमान तैनातीः एसडीएम एटा) विराग पांडेय (वर्तमान तैनातीः एसडीएम गाजियाबाद) व लालता प्रसाद (वर्तमान तैनातीः एसडीएम बुलंदशहर) शामिल हैं। चंदौली के जिलाधिकारी द्वारा पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर तहसील की पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया था।

इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई मामलों में वसूली के नोटिस वापस ले लिए गए हैं। ऐसा तब हुआ जब पूर्व में बेदखली आदेश पारित हो चुके थे। इस मामले में कब्जेदारों को कार्रवाई से बचा लिया गया। इसमें शामिल भूमि खलिहान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, नवीन परती, बंजर एवं लोक उपयोगिता की थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय समिति (एडीएम न्यायिक, एसडीएम चकिया एवं अपर एसडीएम चंदौली) गठित की गई। समिति की विस्तृत जांच में यह स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन तहसीलदारों ने पीठासीन अधिकारी की हैसियत से अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में आदेश पारित किए, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज की ओर से जारी आदेश में तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच शुरू करते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नामित किया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर के तहसीलदार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है। इनके आरोप पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। निलंबन के दौरान तीनों पीसीएस अधिकारी राजस्व परिषद, लखनऊ से संबद्ध रहेंगे।

वीआईपी रौब पर पुलिस की लगाम, अवैध पास और हूटर पर कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात ब्रेकिंग न्यूज़

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली पुलिस ने बुधवार को नगर क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया।अभियान के दौरान वाहनों में लगे अवैध हूटर और वीआईपी पास हटवाए गए। साथ ही शीशों पर लगी काली फिल्म भी उतरवाई गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। जांच के दौरान चार वाहनों में अवैध विधायक व वीआईपी पास पाए गए। पुलिस ने मौके पर ही पास हटवा दिए। कई वाहनों के शीशों पर काली पन्नी लगी मिली।नियमों के उल्लंघन पर चालकों को समझाया गया और काली फिल्म हटवाई गई। कुछ चालकों को सख्त चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। कहा कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नहर माइनर की पटरी कटी, पानी गांवों में घुसा, 50 बीघा फसल जलमग्न

● **गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित**

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के जमुआवा गांव के पास नहर माइनर की पटरी कटने से पानी उफनाकर कान्हमऊ गांव तक पहुंच गया। तेज बहाव के कारण पानी खेतों से निकलकर ग्रामीणों के दरवाजों तक भर गया। पानी भरने से करीब 50 बीघा गेहूं और सरसों की फसल प्रभावित हुई। हालांकि समय रहते नहर विभाग ने कुलाबा बंद कराकर स्थिति पर काबू पा लिया। मंगलवार की रात जमुआवा गांव के निकट नहर माइनर की पटरी अचानक कट गई। इससे नहर का पानी आसपास के खेतों में फैल गया। पानी भरने से जमुआवा गांव के रत्नेश, शिवकुमार, भगवती सोनी, रामकुमार, मोहित सविता, शैलेंद्र, पवन यादव, पिंटू सविता, भुल्लन, बालकृष्ण चौरसिया और इंद्रपाल यादव के खेत जलमग्न हो गए। गेहूं और सरसों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। ढलान अधिक होने के कारण पानी आगे बढ़ता चला गया। इससे कान्हमऊ गांव के भुल्लन, शैलेंद्र और नीरज के घरों तक पानी पहुंच गया।ग्रामीणों के दरवाजों पर पानी भर गया। दरवाजों के पास बने प्रसाधन के गड्ढों में पानी भर गया। घरों के बाहर रखी सूखी लकड़ियां, भूसा और उपले भीग गए। इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि खेतों और दरवाजों के सामने पानी भर गया। इससे उन्हें निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ा। कई ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों बाद नहर का पानी उनके गांव तक पहुंचा है। इससे खेतों को नमी मिली है। उनका कहना है कि इससे भूमि का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। नहर विभाग के अवर अभियंता सौरभ कुमार ने बताया कि दो दिन पहले नहर की टेल बंद कराई गई थी। आशंका है कि किसी शरारती तत्व ने उसे खोल दिया। दिनेश तिवारी के खेतों के पास पटरी के कुलाबे से पानी निकलकर गांव की ओर बढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर टीम भेजकर कुलाबा बंद करा दिया गया। अवर अभियंता ने बताया कि जहां जहां कहीं पटरी कटने की संभावना दिखाई दी उसकी भी मरम्मत करा दी गई है।

विकास खंड के सभी प्रधानाध्यापकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज रायबरेली। कस्बा स्थित राजकीय बालिका इंटर कालेज के सभागार में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्षों, सदस्यों और विकास खंड के सभी प्रधानाध्यापकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के सुचारु संचालन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विद्यालय व समाज के बीच सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना था।खंड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होती है। उन्होंने जोर दिया कि समिति के सक्रिय सहयोग से ही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष विनोद अवस्थी ने प्रशिक्षण के दौरान समिति की भूमिका, दायित्वों और अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने, बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता तथा सकारात्मक शैक्षिक वातावरण तैयार करने में एसएमसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में उपस्थित जूनियर शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष शिव बालक ने प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंध समिति के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह समन्वय आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालय राघवपुर के एसएमसी अध्यक्ष अरविंद मौर्य ने आए हुए प्रधानाध्यपकों व एसएमसी अध्यक्षों से पारदर्शिता, जवाबदेही और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया।प्रशिक्षण के विभिन्न सत्रों में शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं, स्कूल प्रबंधन, वित्तीय प्रावधानों और बच्चों के सर्वांगीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। एक दिवसीय कार्यक्रम में ए आर पी विकास चौधरी, मीनाक्षी पाण्डेय, सरोज कुमार, ने सभी को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर दिनेश शुक्ला, सुरेंद्र शर्मा, मनीष सिंह, दयाशंकर अवस्थी, नीता पाण्डेय, उषा सिंह समेत सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक व एसएमसी अध्यक्ष मौजूद रहे।

अनियंत्रित होकर खाई में पलटी यात्रियों से भरी बस, मची चीख-पुकार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोन (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के खेमपुर में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेलगुड़वा से यात्रियों को लेकर कोन की ओर आ रही एक निजी बस स्टेयरिंग फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। हादसे के वक्त बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अपनी सामान्य गति से जा रही थी कि तभी अचानक खेमपुर के पास बस की स्टेयरिंग फेल हो गई। चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दुर्घटना होते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत कोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया। दर्जनों यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। दो यात्रियों में से एक हालत चिंताजनक बनी हुई है। चिकित्साधिकारी डॉ. जे.पी. सिंह ने बताया कि घायल मखन्नचू (उम्र 65 वर्ष), निवासी डाल्टेनगंज, के सिर में गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या बस की फिटनेस और तकनीकी रखरखाव में कोई कमी थी।

अंधेर नगरी, चौपट आयोग, अखिलेश ने कहा- चुनाव आयोग का कोई झंडा हो तो भाजपा कार्यालय पर लगा दें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण में फर्जी फार्म-7 के सहारे अल्पसंख्यकों को वोट काटने की भाजपा की साजिश के आरोप के साथ गुरुवार को निर्वाचन आयोग पर करारा हमला बोला। एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की। 'अंधेर नगरी, चौपट आयोग' लिखकर तंज करते हुए कहा कि चुनाव का कोई झंडा हो तो वो उसे भाजपाइयों के घर पर लगा दे। सपा प्रमुख ने मामले में सर्वोच्च न्यायालय से भी संज्ञान लेने की मांग की। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, 'अब बस यही बचा है कि चुनाव आयोग भाजपाइयों के घर पर बूथ बना दे और भाजपाइयों को पीठासीन अधिकारी। क्या चुनाव आयोग ने भाजपा को ठेके पर अपना काम दे दिया है या भाजपा ने चुनाव आयोग को संविदा पर रख लिया है। सरेआम वोट काटने-बढ़ाने का अपराध हो रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को ये नजर नहीं आ रहा। आज वोट छीनने वाले कल को जनता का बाकी सब भी छीन लेंगे।'

एक अन्य पोस्ट में अमेठी के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मामले से जुड़ा वीडियो पोस्ट कर लिखा, 'सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी, बीएलओ को प्रताड़ित करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोट काटने की साजिश कर रहे हैं।' वहीं गुरुवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को ज्ञापन भेजकर विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में सपा समर्थक पीडीए और अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने के लिए प्रिंटेड फार्म-7 जमा करने की शिकायत की है। ऐसे फार्म निरस्त करने और आवेदकों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

योगी आदित्यनाथ सरकार का दिव्यांगजनों को रोजगार देने का विशेष अभियान 13 तक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगजनों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को रोजगार और स्व-रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 की शुरुआत हो गई है। यह विशेष अभियान छह फरवरी से 13 फरवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत बीते तीन वर्षों में कौशल विकास मिशन और राजकीय आइटीआइ से प्रशिक्षित योग्य एवं इच्छुक दिव्यांगजनों को सेवायोजन का अवसर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिलों में उपलब्ध अन्य इच्छुक दिव्यांगजन भी इस अभियान का लाभ ले सकेंगे। अभियान के दौरान जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों और अन्य अधिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजनों का नियोजन कराया जाएगा। इस अभियान के साथ ही एमएसएमई, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र व अन्य विभागों की स्व-रोजगार योजनाओं से भी इच्छुक दिव्यांगजनों को जोड़ा जाएगा। यह अभियान हर जिले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति संचालित कर रही है। समिति में जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला रोजगार सहायता अधिकारी और कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक शामिल होंगे। राजकीय आइटीआइ को केंद्र बनाकर रोजगार और स्व-रोजगार से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकृत दिव्यांगजनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा और जिला रोजगार सहायता अधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध नौकरियों से जोड़ा जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

पूर्व महापौर के सोशल मीडिया पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज

ब्यूरो प्रयागराज। यह कार्रवाई प्रयागराज की पूर्व महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अभिलाषा गुप्ता नन्दी के सोशल मीडिया पेज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई। मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व धमकी भरे शब्दों का प्रयोग किया गया था। इस मामले में पूर्व महापौर की मीडिया सलाहकार पूनम अग्रवाल ने कोतवाली में तहरीर देकर संबंधित युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। तहरीर में बताया गया कि पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नन्दी एक कर्मठ, परिश्रमी और समर्पित जनसेवक के रूप में जानी जाती हैं। उनकी सामाजिक एवं सार्वजनिक गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान में उनके फेसबुक पेज पर लगभग 3 लाख 57 हजार फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, जबकि इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी लाखों की संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं। शिकायत के अनुसार, बीते दो-तीन दिनों से 'शैलेश श्रीवास्तव' नामक फेसबुक आईडी से उनके विभिन्न पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अत्यंत आपत्तिजनक और भय पैदा करने वाली टिप्पणियां की जा रही थीं। टिप्पणी में कथित रूप से मंत्री नन्दी को लेकर आपत्तिजनक भाषा और धमकी का प्रयोग किया गया, जिससे मानसिक आघात पहुंचा है। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2010 में मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी पर आरडीएक्स रिमोट बम से प्राणघातक हमला हो चुका है, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार और एक सिविल गनर की मृत्यु हुई थी। उस प्रकरण का ट्रायल इस समय अंतिम चरण में है। ऐसे संवेदनशील समय में की गई इस तरह की टिप्पणियों को गहरी साजिश का हिस्सा मानते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव का नाम बना अभिशापः बलिया का 'रूपवार तवायफ' सामाजिक तिरस्कार से जूझ रहा

बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो समाज की सोच और प्रशासनिक व्यवस्था–दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिले का एक गांव अपने नाम की वजह से वर्षों से सामाजिक तिरस्कार और मानसिक पीड़ा झेल रहा है। गांव का नाम है रूपवार तवायफ। नाम में जुड़ा 'तवायफ' शब्द आज यहां के लोगों के लिए सम्मान नहीं, बल्कि एक अभिशाप बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव पूरी तरह सामान्य है, यहां रहने वाले लोग मेहनतकश, पढ़े-लिखे और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने गांव का नाम बताते हैं, सामने वाला व्यक्ति अजीब नजरों से देखने लगता है। इससे उन्हें शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ता है। गांव के युवाओं का कहना है कि यह नाम उनके भविष्य में बड़ी बाधा बन रहा है। नौकरी के लिए आवेदन करते समय, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरते वक्त या किसी सरकारी प्रक्रिया में जब गांव का नाम दर्ज करना पड़ता है, तब कई बार उन्हें मजाक, तंज और अपमान झेलना पड़ता है। कुछ युवाओं का दावा है कि साक्षात्कार के दौरान भी इस नाम को लेकर असहज सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों में गांव का नाम इसी तरह दर्ज है। लोग अक्सर पूछ बैठते हैं कि यह कैसा नाम है, जिससे उन्हें हिचकिचाहट और मानसिक पीड़ा होती है। खासकर बेटियों के लिए यह नाम और भी बड़ी समस्या बन गया है। गांव वालों का कहना है कि रिश्ते तय करने में इस नाम की वजह से कई बार बात आगे ही नहीं बढ़ पाती। ग्रामीणों का मानना है कि गांव का यह नाम शायद किसी पुराने ऐतिहासिक या सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, लेकिन आज की पीढ़ी का उससे कोई लेना-देना नहीं है। यहां के बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनना चाहते हैं तथा सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। गांववासियों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव के नाम पर पुनर्विचार किया जाए और इसे बदला जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस मानसिक बोझ और सामाजिक तिरस्कार से मुक्ति मिल सके। उनका कहना है कि नाम बदले बिना सम्मान की राह आसान नहीं होगी।

प्रभात नमकीन एंड स्नैक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को दुबई में मिला बिज़नेस एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली! व्यापार को बढ़ावा देने की पहल तहत अमर उजाला बिज़नेस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026 का भव्य आयोजन दुबई के रेडिसन ब्लू डीरा क्रीक में सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित समारोह में प्रभात नमकीन एंड स्नैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा को उनके उत्कृष्ट व्यावसायिक योगदान के लिए बिज़नेस एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया गया। इस समारोह में रिटेल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 35 उत्कृष्ट उद्यमियों और संस्थानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमाल सईद अहमद बुजंजाल अल एवं विशिष्ट अतिथि कैप्टन प्रदीप सिंह ने पुरस्कार प्रदान करते हुए विजेताओं के उद्योग विकास और सामाजिक प्रभाव में योगदान की सराहना की। समारोह में भारत एवं विदेशों से आए प्रतिष्ठित उद्यमी, शिक्षाविद्, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बिज़नेस लीडर्स की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमर उजाला का प्रतिनिधित्व अशोक शर्मा हेड स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग और सचिन नरंग एवीपी सेल्स ने किया, जिनकी सक्रिय भूमिका से आयोजन अत्यंत सफल रहा। दुबई को इस आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया, जो अपनी वैश्विक कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक अवसंरचना और व्यापार-अनुकूल वातावरण के लिए जाना जाता है। बिज़नेस एक्सीलेंस अवॉर्ड्स का उद्देश्य भारतीय उद्यमों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सतत विकास के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना है। दुबई संस्करण ने एक बार फिर सीमाओं से परे उत्कृष्टता को सम्मानित करने की अमर उजाला की प्रतिबद्धता को मजबूती से स्थापित किया।

फूलपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 15 बोरी(5 क्विण्टल) धान बरामद

ब्यूरो प्रयागराज। थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-45/ 2026 धारा-305क/ 331(4) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कल्लू गिरि उर्फ अर्जुन गिरि उर्फ शंकर गिरि पुत्र कन्हैयालाल गिरि निवासी बीबीपुर उग्रसेनपुर थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-05.02.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उग्रसेनपुर के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुए 15 बोरी धान वजन करीब 05 क्विण्टल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि दिनांक-03.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर वादी मुकदमा के गोदाम से करीब 20-30 बोरी धान चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-45/ 2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

चलतीं ट्रेन में चढ़ी महिला का पैर फिसलने से गिरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में चलतीं ट्रेन में चढ़ने के दौरान बुजुर्ग महिला हड़बड़ाहट कर नीचे गिर गई,वह मुंह के बल गिरी,उनका एक हाथ ट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म के बीच फंस गया, वहां मौजूद आरपीएफ के जवान ने तीन सेकेंड में उसे प्लेट फार्म के नीचे जानें से बचा लिया,यह पूरा मामला स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में क़ैद हो गया,इसका वीडियो सामने आया, है यह घटना सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रात दो बजे हुई, पटना जा रही मगध एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ते समय महिला गिर गई, इसके पति की मौत हो गई है,वह पति के जनाजा में शामिल होने के लिए परिवार के साथ जा रही थी, कानपुर के मेस्टन रोड की रहने वाली अनवर जहां अपने परिवार के साथ रहतीं हैं उनके पति इकबाल कुरेशी कुछ दिन पहले पटना गए थे, वहां बुधवार को उनकी मौत हो गई,यह जानकारी कानपुर पहुंची तो परिवार में मातम पसर गया पति इकबाल कुरेशी के जनाजे में शामिल होने के लिए अनवर जहां अपने दोनों बेटों के साथ पटना जा रही थी,रात करीब दो बजे प्लेटफार्म नंबर पांच पर मगध एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से पटना जाने के लिए रवाना हुई,इसी दौरान अनवर जहां ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, इसी दौरान पायदान से पैर स्लिप हो गया,वह मुंह के बल गिर पड़ी, इससे ट्रेन और प्लेटफ़ॉर्म के बीच हाथ फंस गया,इस दौरान डियूटी में मौजूद आरपीएफ जवान विनोद यादव की नजर पड़ी, विनोद ने तत्परता से महिला को बाहर खींच लिया, जिससे महिला की जान बच गई।

नए यमुना ब्रिज की तरह 150 साल से अधिक पुराना रेलवे ब्रिज भी लाइटों से जगमग होगा

ब्यूरो प्रयागराज। नगर निगम ने अन्य पुलों की तरह यमुना पर बने पुराने पुल पर भी लाइटें लगाने की तैयारी कर ली है। पुल पर लाइटें लगाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने एनसीआर के अफसरों से बात की है। बताया जा रहा है कि रेलवे के अफसरों ने पुल पर लाइट लगाने की मौखिक स्वीकृति दे दी है। लाइट लगाने को लेकर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने बताया कि दो टायर वाले शहर के सबसे पुराने पुल पर अंधेरा रहता है। ऊपरी टायर से ट्रेनें जाती हैं। पुल के लोअर टायर से छोटे वाहनों की आवाजाही होती है। सूर्यास्त के बाद पुल से वाहन अंधेरे में आवागमन करते हैं। पुल पर लाइट लगाने की लगातार मांग हो रही है। नगर निगम लाइट लगाने के लिए तैयार है। रेलवे के अफसरों से पुल की सड़क मरम्मत करने का भी आग्रह किया गया है। महापौर ने अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया है। अपर नगर आयुक्त रजीव कुमार शुक्ल ने बताया कि पुराने यमुना पुल के पास रौनक बढ़ गई है। पुल के पास ही शाम को लेजर शो देखने लोग जाते हैं। वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का संचालन भी पुल के पास हो रहा है। ऐसे में लाइट लगने से शहर के सबसे पुराने पुल की खूबसूरती बढ़ जाएगी।

पंचायत सचिव खोजवा ड्यूटी के दौरान शराब ठेके से एक पेटी शराब लेते हुए वीडियो वारयल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत करकटी के सचिव का वीडियो हुआ वायलर , जिसमें वीडियो में साफ दिख रहा हैं कि पंचायत करकटी के सचिव खोजवा चर्मकार शराब दुकान से एक पेटी शराब ले जाते हुए दिख रहे हैं।जिनके पास ग्राम पंचायतों के शिकायतें को निराकरण करने का समय नहीं वही दूसरी ओर सचिव साहब शराब की पेटी ले जा रहे हैं। ग्राम पंचायत करकटी का यह कोई पहला मामला नहीं जो अधिकारी नजर अंदाज कर रहे हैं लगातार पत्राचार के माध्यम से सचिव व सरपंच की शिकायतों के बाद भी सचिव की जुगाड़ काम आ जाता हैं।

दर्जनों शिकायतें से परे पंचायत पर निपटारा के लिए नहीं समय

जनपद सोहागपुर के ग्राम पंचायत करकटी में पंचायतों में हो रहे कार्यों में भारी लापरवाही लगातार सामने आ रही जिसमें कई तो लिखित शिकायत तक हुई हैं लेकिन कार्यवाही व जाँच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इसमें से आधे शिकायत तो सीएम हेल्पलाइन में हुआ था। लेकिन न जाँच न कार्यवाही बस फोर्सक्लोज कर निपटारा कर दिया जाता हैं। इनका कहना हैं जिला पंचायत सीईओ शिवम प्रजापति जब इस संबंध में जानकारी पूछा गया तो बोले वीडियो भेज दीजिए वीडियो देखने के बाद हम उचित कार्यवाही करेंग।

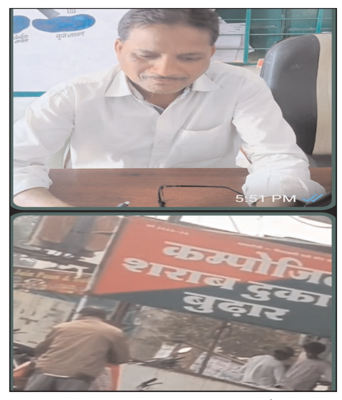

22 फरवरी 2026 को कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही में मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु सीडीओ ने की बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भदोही/ उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद भदोही में दिनांक 22 फरवरी 2026 को मेगा/ वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रभावी आयोजन हेतु बाल गोविन्द शुक्ल मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता मे संबंधित विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुये शिविर को सम्पन्न कराने हेतु समस्त अधिकारियों के साथ विकास बैठक की गयी। बैठक में समस्त संबंधित अधिकारियों का विभागवार दायित्व निर्धारण करते हुये योजनाओं की सहभागिता, लाभार्थियों की पहचान एवं शिविर के सफल आयोजन से संबंधित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कारपेट एक्सपो मार्ट भदोही निर्धारित स्थल पर सभी विभाग अपने-अपने स्टाल लगायेंगे एवं अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी जनमानस को देने हेतु पम्पलेट, इत्यादि उपलब्ध रखेंगे। साथ ही विभागीय योजनाओं में लाभ दिये गये लाभार्थी सहित अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। कार्यक्रम स्थल पर दिनांक 22 फरवरी.2026 को अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, वी0वी0 राम जी योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री आवास, आरसेटी से प्राप्त प्रशिक्षण के लाभार्थी, सी0एम0 यूवा योजना, कौशल विकास, युवा कल्याण, पर्यटन संस्कृति, बेसिक शिक्षा, विद्युत विभाग, दिव्यांग कल्याण, आयुष्मान कार्ड, सम्मानित किसान इत्यादि सहित लगभग 2000 लाभार्थी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर लाभार्थियों एवं जनमानस की सुविधा हेतु योजनाओं के शिविर लगाये जायेंगे। योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

साथ ही सुरक्षा का पुक्ता इंतजाम होगा एवं आकस्मिक चिकित्सा के लिए चिकित्सक दल, एम्बुलेन्स तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश संबंधितों को दिया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि मोहन लाल मिश्रा, संदीप एवं जनपद के सभी अधिकारी उपस्थित रहें।

ट्रेड डील पर राज्यसभा में बोले पीएम मोदी- वोट बैंक की राजनीति से नहीं, मजबूत इकोसिस्टम से होती है डील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक भूमिका पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के साथ विश्व का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल है, जो वैश्विक चुनौतियों को मात दे रहा है. भारत आज कई देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर विश्वमित्र बन रहा है।

पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण में विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया. पीएम ने कहा किहमारे पास आज दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट है. विश्व में आज जो चुनौतियां पैदा हो रही हैं, भारत उनका निवारण करने वाला देश है. भारत की ग्रोथ हाई और इन्फ्लेशन लो है. ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि ट्रेड डील मजबूत इकोसिस्टम होती हैं ना कि वोट बैंक की राजनीति से. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है. सबका झुकाव भारत की ओर है. भारत आज विश्व मित्र के रूप में अनेक देशों का भरोसेमंद पार्टनर बना है. आज पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की चर्चा करती है, जिसके सूत्रधार के रूप में भारत बुलंद आवाज बन गया है।

आज फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर रहा है भारत

पीएम मोदी ने कहा, आज भारत अनेक देशों के साथ फ्यूचर रेडी ट्रेड डील कर रहा है. दुनिया के 9 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील की गई है. इसमें मदर ऑफ आल डील्स भी है. पीएम ने विपक्ष पर तंज कसा- जो लोग थक गए और चले गए उनको एक दिन जवाब देना होगा कि दुनिया का कोई देश हमसे डील क्यों नहीं कर रहा था।

वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने कभी सोचा ही नहीं

उन्होंने कहा, दुनिया के देश हमारे साथ ऐसे ही आज डील नहीं कर रहे हैं. जब डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करती हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात है. वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोगों ने देश के लिए कभी सोचा ही नहीं. जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से भाषण दिए, उन्हें देख लो. उनके पास कोई विजन नहीं था।

बड़े-बड़े देश हमसे संबंध रखने के लिए आतुर

पीएम मोदी ने कहा, आज के भारत की कोशिशों का नतीजा है कि बड़े-बड़े देश हमसे संबंध रखने के लिए आतुर हैं. ईयू के साथ ट्रेड डील हो या अमेरिका के साथ, पूरा विश्व ट्रेड डील की तारीफ कर रहा है.जब ईयू के साथ ट्रेड डील हुई तो पूरी दुनिया को यकीन हुआ कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता बढ़ेगी. अमेरिका के साथ डील होने पर ये यकीन और मजबूत हुआ।

एपस्टीन फाइल्स पर घबरा क्यों रहे हैं? पीएम मोदी पर संजय सिंह का पलटवार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर पलटवार किया है. उन्होंने एपस्टीन फाइल्स पर सवाल पूछा था. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं. उन्होंने कहा कि हम देश को अमेरिका के हाथों गिरवी नहीं रखने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल भी क्यों न जाना पड़े। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री जी का ऐसा बयान उनकी बौखलाहट को दिखाता है. एपस्टीन फाइल्स पर सवाल पूछा तो पीएम घबरा क्यों रहे हैं? सवाल यह है कि उन फाइलों में ऐसा क्या है जिससे सरकार असहज हो रही है? संजय सिंह ने कहा, क्या इसी दबाव में प्रधानमंत्री जी ट्रंप के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं? देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने नहीं देंगे. चाहे इसके लिए मुझे फिर जेल ही क्यों न जाना पड़े. आज प्रधानमंत्री ने मुझ पर, अरविंद केजरीवाल पर और हमारी पार्टी पर संसद में जमकर हमला किया. ये उनकी बौखलाहट दिखाता है. प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि मैंने संसद में उनसे एपस्टीन फाइल्स पर सफाई मांगी।

एपस्टीन फाइल्स में ऐसा क्या ?

आम आदमी पार्टी सांसद ने सवाल किया, एपस्टीन फाइल्स में ऐसा क्या है जिससे प्रधानमंत्री इतना बौखला रहे हैं? क्या इसी वजह से वे ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं? इससे पहले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में भी एपस्टीन आईलैंड जैसे हालात बन रहे हैं?

दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोग गायब

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुनियाभर में एपस्टीन फाइल्स की चर्चा चल रही है. इस फाइल में खुलासा हुआ है कि एक प्राइवेट आईलैंड पर नाबालिग लड़कियों को रखा जाता था और उनका रेप किया जाता था.वहीं अब दिल्ली में इस साल के पहले 15 दिनों में 800 से ज़्यादा लोग गायब हुए हैं और इसमें से ज्यादातर बच्चियां हैं. दिल्ली में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद दिल्ली पुलिस इनका पता नहीं लगा सकी है।

पूरे देश में बच्चों को उठाया जा रहा

इससे इतर पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सदन में कहा,दिल्ली समेत पूरे देश में बच्चों को उठाया जा रहा है. हर साल हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं और इसमें 72% बच्चियां हैं. एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार, देश में हर 8 मिनट के अंदर एक बच्चा गायब हो रहा है. इसमें भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बच्चे ग़ायब हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश का गौरव बने प्रयागराज के डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी

● पैरा डार्ट्स चैंपियनशिप मलेशिया के लिए चयन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। दिव्यांगजन सशक्तिकरण, खेल प्रतिभा और मानवीय संकल्प के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि प्रयागराज स्थित नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, जमुनीपुर के विशेष शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी ने पैरा डार्ट्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित की है। इंडियन डिसएबिलिटी डार्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय पैरा डार्ट्स चैंपियनशिप 2026, जो दिनांक 31 जनवरी एवं 1 फरवरी 2026 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में संपन्न हुई, में डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर से 120 से अधिक दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जहाँ डॉ. त्रिपाठी ने अपने कौशल, एकाग्रता और अनुशासन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके इसी शानदार प्रदर्शन के परिणामस्वरूप वर्ल्ड डिसेबिलिटी डार्ट्स एसोसिएशन, स्कॉटलैंड द्वारा आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय पैरा डार्ट्स चैंपियनशिप (मलेशिया) के लिए उनका चयन किया गया है। इस प्रकार डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी अब वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो न केवल प्रयागराज और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। इंडियन डिसएबिलिटी डार्ट्स एसोसिएशन के महासचिव श्री महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. त्रिपाठी का चयन उनकी निरंतर साधना, अनुकरणीय अनुशासन और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन का प्रतिफल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ. त्रिपाठी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपने प्रदर्शन से राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी केवल एक सफल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के मार्गदर्शक, प्रेरक और सशक्तिकरण के संवाहक भी हैं। वे सदैव इस संकल्प के साथ कार्यरत हैं कि सभी दिव्यांगजन शैक्षिक एवं खेल दोनों ही क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त कर विश्व मंच पर आगे बढ़ें। उनका प्रयास केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित न होकर, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में निरंतर समर्पित है। शैक्षणिक जगत में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका और खेल के मैदान में यह उपलब्धि डॉ. त्रिपाठी की बहुआयामी प्रतिभा, दृढ़ इच्छाशक्ति और मानवीय संवेदना को सशक्त रूप से रेखांकित करती है। उनकी यह सफलता विश्वविद्यालय परिवार, प्रयागराज जनपद एवं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय होने के साथ-साथ उन असंख्य दिव्यांगजनों के लिए आशा, साहस और प्रेरणा का संदेश है। विश्वास है कि डॉ. दीपक कुमार त्रिपाठी का यह अंतरराष्ट्रीय पदार्पण दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में एक नई राह प्रशस्त करेगा और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, खेल और राष्ट्रसेवा के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

UP के गांव हो रहे हाईटेक, प्लास्टिक कचरे से बनाई 75 किलोमीटर लंबी सड़क

● राजधानी लखनऊ समेत रामपुर, अमेठी, ललितपुर और एटा में प्लास्टिक कचरे से अब तक 75 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की जा चुकी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का नया मॉडल पेश कर रही हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश के गांव अब स्वच्छता और नवाचार की नई पहचान गढ़ रहे हैं. प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण, घर-घर कूड़ा एकत्र कर उससे खाद निर्माण और आय सृजन के प्रयोगों ने प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को हाईटेक बना दिया है. राजधानी लखनऊ समेत रामपुर, अमेठी, ललितपुर और एटा में प्लास्टिक कचरे से अब तक 75 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार की जा चुकी हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का नया मॉडल पेश कर रही हैं।

वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर काम

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में वेस्ट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत ग्राम पंचायतों में घर-घर से कूड़ा संग्रहण शुरू कर वर्मी खाद का उत्पादन किया जा रहा है. इस पहल से अब तक 3 करोड़ रुपए से अधिक की आय सृजित हो चुकी है. वहीं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों से 29 लाख रुपए की अतिरिक्त कमाई की गई है. इस योजना के तहत पंचायतीराज विभाग प्रदेश में वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर काम कर रहा है।

प्रदेश के हर गांव में किया जाएगा अभिनव प्रयोग

पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ गांव महाभियान के तहत कूड़े को संसाधन में बदला जा रहा है. प्लास्टिक कचरे का सदुपयोग कर सड़क निर्माण, जैविक कचरे से खाद उत्पादन और पंचायतों की आय बढ़ाने के ये प्रयोग प्रदेश के हर गांव को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं. इस योजना के जरिए प्रदेश के हर गांव में अभिनव प्रयोग किए जाएंगे।

प्लास्टिक वेस्ट का यूटिलाइजेशन

पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, विभाग ग्राम पंचायतों को नवाचार के माध्यम से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. गांव-गांव स्वच्छता अभियान के साथ प्लास्टिक वेस्ट के यूटिलाइजेशन से न केवल पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, बल्कि करोड़ों रुपये की आय भी सृजित हो रही है।